

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)



Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1283 /SEIAA/ 22

Date: 4/8/22

प्रति,

मेसर्स आकाश ग्रेनाईट,
प्रोप. श्री दिनेश चंद गुप्ता,
निवासी इन्द्रानगर, कवरई,
जिला महोबा (उ.प्र)

विषय:- प्रकरण क्र. 9258/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट, प्रोप. श्री दिनेश चंद गुप्ता, निवासी इन्द्रानगर, कवरई, जिला महोबा (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 499, ग्राम घटहरी, तहसील गौरीहर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

Prescribing of TOR

संदर्भ:-738वी SEIAA बैठक दिनांक 28.07.2022 एवं 585वी SEAC समिति बैठक दिनांक 13.07.2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 585वीं बैठक दिनांक 13.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

A. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.07.2021 के अनुसार Violation के प्रकरणों में Polluter Pays सिद्धान्त आधारित SOP के परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2014 से 2020 तक किये गये उत्खनन कार्य का विस्तृत विवरण ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करें कि किस वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में खनिज निकाला गया है। उक्त विवरण खनिज विभाग से प्रमाणित कराया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
3. साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
4. परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का खनन कार्य न करे। चल रहे खनन कार्य तत्काल बंद करे।

5. साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैधानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लंघन की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्यवाही हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया जाये।

B. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 585वीं बैठक दिनांक 13.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा में निहित शर्तें क्र. 01 से 18 तक को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित की जायेगा।
- (viii) चूना पत्थर/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/पत्थर आदि जैसे पत्थरों का प्रमाणन/अध्ययन किया जाना चाहिए (प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है) कि इसे अन्य उद्योगों जैसे कि रसायन, सीमेंट और फर्श आदि के उपयोग हेतु अनुपयुक्त माना गया है इसलिये इसका उपयोग गिट्टी बनाने हेतु किया जा सकता है।
- (ix) मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

- (x) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- (xi) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- (xiii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये ।
- (xvi) Project description, its importance and the benefits.
- (xvii) Some Shed (on 90 meters SW) are observed in the western side of the lease PP shall discussed their protection plan with their clear status and photos that what for these sheds are constructed and what is their present use.
- (xviii) Similarly, protection plan for temple at 300 meters on northern side and road on north-west side at a distance of 100 meters shall also be discussed in the EIA report.
- (xix) Inventory of all existing trees with their girth and height details and if any tree is to be uprooted, then its proper management plan it should be clearly addressed in EIA.
- (xx) Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage).
- (xxi) Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
- (xxii) Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.

- (xxiii) Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
- (xxiv) Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
- (xxv) Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
- (xxvi) Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
- (xxvii) Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
- (xxviii) During EIA study, 04 to 05 trial pits (out of which one shall be in the barrier zone of the lease area) shall be dug and soil profile be studied for proposing plantation as per the soil quality.
- (xxix) PP shall also submit the year wise details of mineral excavated with credible proof of royalty deposited from competent authority.
- (xxx) PP shall provide an elaboration of the cost benefit analysis in terms of loss of natural resources and nearby vegetation area, agricultural area vs mineral benefit along with eco-system services such as soil loss, water percolation, fodder availability, habitat loss and flora & fauna due to mining.
- (xxxi) Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- (xxxii) Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- (xxxiii) The details as per step 12 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 shall be furnished with EIA report with credible documentary evidences.

Documents to be submitted:
Environmental Consultant / PP

- I. A certificate from the Consultant shall be submitted that they have been accredited by MoEF (Gol), as per OM.
- II. The Project Proponent shall submit an undertaking as part of EIA report regarding data authenticity and owning the contents of EIA report as per OM dated 05/10/2011.

- III. Final EIA report including public hearing and EMP various aspects should be submitted to the SEIAA.
 - IV. All information with supporting documents as prescribed by SEIAA in the O.M. No. 966 dated 27/01/2012 has to be furnished with the EIA report. Failing this the EIA report shall be returned to the PP.
 - V. Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for the project should be provided.
 - VI. PP should provide latest notarized copy of KhasraPanchsala (P-II) indicating ownership. If the ownership is different than a notarized copy of the agreement should be submitted. Besides, notarized copy of the lease agreement should also be submitted clearly indicating sanction period & ownership.
 - VII. Notarized copy of the approved mining plan.
 - VIII. Location of National Parks, Sanctuaries, biosphere Reserves, Wildlife corridors, Tiger reserves (existing as well as proposed), if any, within 10 km of the mine lease should be clearly indicated. A location map duly authenticated by Chief Wild life Warden and recommendation/ comments of Chief Wildlife Warden of concerned district should also be provided in this regard.
 - IX. A letter from District Collector Office / Executive Engineer PWD indicating distance of mine area from inter-state boundary and critically polluted/ sensitive areas notified by CPCB/MoEF.
 - X. DFO letter indicating the distances of nearest forest boundary from the boundary of the proposed site.
- * In case the distance of nearest forest boundary is up to 250 meters or less, then NOC as per orders issued by forest department from time to time is required.
- XI. NOC from Gram Sabha if located in scheduled notified area.
 - XII. Other mandatory permissions and clearances from various authorities.
 - XIII. All TOR prescribed in the standard TOR published by MoEF&CC shall be applicable.

Other points to be addressed in the EIA/EMP report:

- Recent land use features in the region.
- Map Depictions: Coloured maps depicting land-use of the region showing sensitive / fragile features and detailed lay-out of the site clearly showing green-belt (existing & planned).
- Location is also to be shown in Tehsil map procured from revenue department, showing exact distances of highway, railway & habitat and all other sensitive area from the site.
- Details of land to be provided in following format:

S.No.	Tehsil	Village	Khasra No.	Area	Ownership	Land use

- Compliance of the conditions laid in the consent / EC should be supported with photograph of the site clearly showing plantation etc (if any).
- Summary of EIA / EMP has to be provided separately along with the EMP detailing impacts, impact zone and mitigations has to be furnished in the following format:

AIR Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

WATER Environment



SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

LAND Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

NOISE Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

Details of Public Hearing Proceedings

SN	Issues raised (details thereby)	Response of Proponent	Comments

- To-the-scale map showing locations of all the mines in 500m radius around the site have to be furnished.
- Source of water for the project with permission / commitment from the competent authority to be submitted.
- Water consumption in the project has to be evaluated including all the usages.

General Conditions

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.



14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analysed.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "UjjwalaYojna .



30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. **Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:**
- Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "UjjwalaYojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. **Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :**
- Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned/Gram Panchayat/ Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest



land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP

35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश:-

- i. स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- ii. विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- iii. पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- iv. पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- v. भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- vi. रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य:-

सं	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से.मी.
2	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी. गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

vii. बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख:-

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।


FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.

37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

Validity:-

- ❖ The TORs prescribed for the project will be valid for a period of Three years for submission of EIA and EMP report accordingly, the TORs will lapse after 27.07.2025
- ❖ This period of validity could be extended by the Regulatory Authority concerned by a maximum period of one year provided an application is made by the applicant to the Regulatory Authority before the expiry of validity period, together with updated Form-I based on proper justification and also recommendation SEIAA/SEAC.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

Endt No. 1284/ SEIAA/22

Dated: 4/8/22

Copy to:-

1. सदस्य सचिव, SEAC, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
5. संबंधित फाईल।

सदस्य सचिव

